राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. आपराधिक विविध (याचिका) संख्या 8723/2022

1.जसवंत सिंह पुत्र स्व. माखन सिंह, उम्र लगभग 34 वर्ष, 2 एसटीबी, तह. विजयनगर, जिला. श्रीगंगानगर.

2. बलवंत सिंह पुत्र स्व. माखन सिंह, उम्र लगभग 37 वर्ष, 2 एसटीबी, तह. विजयनगर, जिला. श्रीगंगानगर.----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, पीपी के माध्यम से

2. सुगन सिंह पुत्र स्व. कालू सिंह, 2 एसटीबी, तह. श्रीविजयनगर, जिला. श्रीगंगानगर।----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता(ओं) के लिए: श्री जे.आर. सरन

श्री बी.एस. राठौड़

प्रतिवादी के लिए: श्री एच.एस. जोधा, पी.पी

श्री एस.के. वर्मा, प्रतिवादी संख्या 2 के लिए।

माननीय न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

17/09/2024

1. यहां आईपीसी की धारा 406, 420 और 120-बी के तहत अपराधों के लिए पुलिस स्टेशन श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर में दर्ज एफआईआर संख्या 371/2022, दिनांक 10.11.2022 को रद्द करने की मांग की गई है।

2. संक्षेप में, प्रासंगिक तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 की मां के पास चक 2 एसटीबी में 1.3920 हेक्टेयर खातेदारी भूमि थी और उसने इसे बेचने में रुचि व्यक्त की थी। उक्त भूमि में से 0.633 हेक्टेयर भूमि याचिकाकर्ता संख्या 1 के नाम पर उसकी मां सरजीत कौर द्वारा उपहार-पत्र के माध्यम से हस्तांतरित की गई थी। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता संख्या 1, सरजीत कौर (याचिकाकर्ता संख्या 1 की मां) और प्रतिवादी संख्या 2, शिकायतकर्ता के बीच 1.3920 हेक्टेयर भूमि के संबंध में बिक्री के लिए एक समझौता किया गया, जिसकी कुल कीमत 68 लाख रुपये थी, जिसमें से 7,50,000/- रुपये 02.05.2022 को समझौता निष्पादित करते समय अग्रिम भुगतान किया गया था। बिक्री विलेख 05.06.2022 तक पंजीकृत होना था, अर्थात लक्ष्य तिथि।

2.1. कथित तौर पर जब प्रतिवादी संख्या 2 ने बिक्री विलेख पंजीकृत करने के लिए याचिकाकर्ता संख्या 1 और उसकी मां सरजीत कौर से संपर्क किया, तो उसने पाया कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने विवादित भूमि के एक हिस्से (0.2530 हेक्टेयर) के संबंध में अपने भाई, याचिकाकर्ता संख्या 2 के पक्ष में दिनांक 12.07.2022 को एक उपहार विलेख के माध्यम से एक उपहार विलेख निष्पादित किया था। प्रतिवादी संख्या 2 (शिकायतकर्ता) ने श्री विजयनगर के विद्वान अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से संपर्क किया, जिन्होंने प्रतिवादी संख्या 2 की शिकायत को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच के लिए पुलिस स्टेशन को भेज दिया, जिसके परिणामस्वरूप संबंधित एफआईआर दर्ज की गई।

3. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील और साथ ही विद्वान सरकारी अभियोजक और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील की ओर से प्रतिद्वंद्वी तर्क सुने हैं।

4. विद्वान सरकारी वकील ने शुरू में ही कहा कि इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि जांच अभी भी चल रही है और आरोप पत्र उचित समय पर दाखिल किया जाएगा। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यदि अंततः यह पाया जाता है कि कोई अपराध नहीं बनता है, तो उचित रिपोर्ट दाखिल की जाएगी।

5. मैं विद्वान सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के विद्वान वकील के तर्कों से खुद को सहमत नहीं कर पा रहा हूं। जब एफआईआर की सामग्री से स्पष्ट रूप से आपराधिक दोष का कोई मामला नहीं बनता है, तो याचिकाकर्ताओं को आपराधिक कार्यवाही को सहन करने के उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाना चाहिए।

6. स्वीकार की गई स्थिति यह है कि विवाद कृषि भूमि से संबंधित एक समझौते से उत्पन्न हुआ है, जिसके लिए शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता नंबर 1 और उसकी मां के बीच कुल 68 लाख रुपये का समझौता हुआ था। शिकायतकर्ता द्वारा 7,50,000/- रुपए दिए गए थे, और उसके बाद, समझौते के अनुसार, उसे बिक्री विलेख/हस्तांतरण आदि के निष्पादन के लिए आगे बढ़ने के लिए, लक्ष्य तिथि यानी 05.06.2022 को या उससे पहले शेष राशि की व्यवस्था करनी थी।

7. जैसा कि घटनाक्रम सामने आया, ऐसा प्रतीत होता है कि शिकायतकर्ता के पास शेष राशि के लिए वित्तीय क्षमता नहीं थी। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं द्वारा उसे 07.06.2022 की तारीख का कानूनी नोटिस जारी करने के बावजूद, जिसमें उसे आगे आकर समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए कहा

गया था, उसने कोई कदम नहीं उठाया। इतना ही नहीं, उसने आगे कोई समय भी नहीं मांगा और/या कानूनी नोटिस का जवाब देने की परवाह भी नहीं की। याचिकाकर्ता संख्या 1 ने न केवल प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता से समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए कहने का अपना कर्तव्य निभाया, बल्कि समझौते के अपने हिस्से को पूरा करने की अपनी इच्छा भी स्पष्ट रूप से व्यक्त की, इसलिए उसे दोषी नहीं ठहराया जा सकता। स्पष्ट रूप से, प्रतिवादी संख्या 2-शिकायतकर्ता, जिसने मामले में आगे बढ़ने का अपना अधिकार खो दिया है, वह दोषी पक्ष है। वह अपनी गलती का फायदा उठाकर आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं कर सकता, जो प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 406, 420 के साथ धारा 120-बी के प्रावधानों का पूर्ण दुरुपयोग है।

8. इस संदर्भ में, राणा राम बनाम राजस्थान राज्य 1 के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है, जिसका प्रासंगिक विवरण नीचे दिया गया है:

> "22.1. आईपीसी की धारा 405 और 420 दोनों ही अलग-अलग डोमेन में काम करती हैं, यानी सौंपना बनाम प्रलोभन। धारा 405 सौंपने से संबंधित है, जहां पीड़ित संपत्ति सौंपकर आरोपी पर भरोसा करता है, और आरोपी द्वारा इस भरोसे का उल्लंघन सीधे पीड़ित को नुकसान पहुंचाता है। इसके विपरीत, धारा 420 प्रलोभन से संबंधित है, जहां आरोपी सक्रिय रूप से पीड़ित से संपर्क करता है, अक्सर गलत बयानी या धोखे के माध्यम से, जिससे पीड़ित को उसकी ईमानदारी पर गलत विश्वास हो जाता है और वह झूठे बहाने/प्रलोभन के तहत अपनी संपत्ति छोड़ देता है। इसलिए, सौंपना मौजूदा विश्वास के

उल्लंघन पर केंद्रित है, जबकि प्रलोभन में शुरू से ही धोखा शामिल है।

22.2. आसान संदर्भ के लिए, धारा 420 आईपीसी को भी नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

> "एस. 420 छल करना और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना जो कोई छल करता है और इस प्रकार बेईमानी से उस व्यक्ति को प्रेरित करता है कि वह किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंप दे, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी ऐसी चीज को, जो हस्ताक्षरित या मुहरबंद हो और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सके, पूरी तरह से या उसके किसी भाग को बना, बदल या नष्ट कर दे, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

भारतीय दंड संहिता की धारा 420 को भारतीय न्याय संहिता, 2023 में धारा 318 (4) के रूप में यथावत रखा गया है तथा निम्नानुसार पढ़ा जाता है:

> "318. धोखाधड़ी। (4) जो कोई भी धोखा देता है और इस प्रकार बेईमानी से उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करता है, या किसी मूल्यवान प्रतिभूति या किसी ऐसी चीज को, जिस पर हस्ताक्षर या मुहर लगी हो और जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित किया जा सकता हो, पूरी तरह से या उसके किसी भाग

को बनाने, बदलने या नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, तो उसे किसी भी प्रकार के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, और वह जुर्माने से भी दण्डित किया जाएगा।

22.3. इस प्रकार, उक्त प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि धोखाधड़ी का कार्य, जहाँ कोई व्यक्ति किसी को धोखा देता है, ऐसा होना चाहिए, जिसके द्वारा धोखा दिए गए व्यक्ति को निम्नलिखित के लिए प्रेरित किया जाता है:

- किसी संपत्ति को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपना।
- किसी मूल्यवान प्रतिभूति को पूरी तरह से या उसके किसी भाग को बनाना, बदलना या नष्ट करना।
- हस्ताक्षरित, सीलबंद और मूल्यवान प्रतिभूति में परिवर्तित होने में सक्षम किसी भी वस्तु को संशोधित या नष्ट करना। इस प्रकार यह प्रावधान दूसरों को संपत्ति से अलग करने या मूल्यवान दस्तावेजों में परिवर्तन करने के लिए छल का उपयोग करने के गंभीर परिणामों को उजागर करता है।

23. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट है कि पुलिस में दर्ज की गई रिपोर्ट में धारा 406 या 420 आईपीसी या किसी अन्य संज्ञेय अपराध के तहत अपराध किए जाने का खुलासा नहीं होता है।

24. इसके अलावा, एफआईआर दर्ज करने से पहले, ललिता कुमारी (सुप्रा) के मामले में निर्धारित शर्तों/मापदंडों का अनुपालन नहीं किया गया। सबसे पहले, पुलिस में दर्ज रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों को उनके वास्तविक रूप में लिया जाए

तो, आईपीसी की धारा 405 में परिभाषित आपराधिक विश्वासघात के अपराध का खुलासा नहीं हुआ, जो आईपीसी की धारा 406 और आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय है या कोई अन्य संज्ञेय अपराध है। दूसरे, कथित अपराध माल की बिक्री और खरीद के विशुद्ध रूप से वाणिज्यिक लेनदेन से उत्पन्न हुए थे। फिर भी, एफआईआर दर्ज करने से पहले, यह पता लगाने के लिए कोई प्रारंभिक जांच नहीं की गई कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ है या नहीं। अगर जरूरी कार्रवाई की गई होती, तो जाहिर है कि परिणाम अलग होते।

9. राणा राम, ibid में बताए गए तर्क को लागू करते हुए, वर्तमान मामले में भी, धारा 405/406, 420 के साथ धारा 120-बी के कोई तत्व नहीं बनते हैं। इस प्रकार, संबंधित एफआईआर को रद्द किया जाना चाहिए।

10. तदनुसार याचिका स्वीकार की जाती है। पुलिस स्टेशन श्री विजयनगर, जिला श्रीगंगानगर में पंजीकृत एफआईआर संख्या 371/2022, दिनांक 10.11.2022 को रद्द किया जाता है और इसके बाद कार्रवाई की जाएगी।

11. लंबित आवेदन(ओं), यदि कोई हो, का भी निपटारा किया जाएगा।

(अरुण मोंगा),जे

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।